ई-न्यूज

24 न्यूज अपडेट

WebSite.: https://24newsupdate.in

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

उदयपुर, गुरूवार 02 जुलाई 2026

वर्ष 3 अंक 79

देशभर में मानसून का कहर: उत्तराखंड में भूस्खलन से बद्रीनाथ-केदारनाथ मार्ग बाधित, मुंबई में रेड अलर्ट

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली/ देहरादून/ मुंबई/ जयपुर, 3 जुलाई। देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बाधित हो गए हैं। सुरक्षा कारणों से केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के बीच मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने समुद्र में लगभग 15 फीट ऊंची लहरें उठने की चेतावनी देते हुए लोगों से समुद्र तट से दूर रहने की अपील की है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और अन्य पर्वतीय जिलों में लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर पहाड़ दरकने से सड़कें बंद हो गई हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर लगातार पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी है। विभिन्न स्थानों पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बागेश्वर जिले में पेड़ गिरने से पुडकुनी-चलकाना मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। महाराष्ट्र में भी बारिश का असर व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान 172 मिमी वर्षा दर्ज की गई। तेज बारिश के बीच चर्चगेट स्टेशन के समीप एक पेड़ उखड़कर कई वाहनों पर गिर गया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। साकीनाका क्षेत्र में खुले मैनहोल में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अंधेरी सब-वे में जलभराव के कारण उसे एहतियातन बंद कर दिया गया है। वहीं नवी मुंबई में जलभराव के दौरान करंट फैलने से दो छात्राएं इसकी चपेट में आ गईं। बीएमसी ने दोपहर के समय समुद्र में करीब 15 फीट ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को समुद्र किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में भी बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है। इंदौर में तेज बारिश के दौरान एक कार नाले में गिर गई, जबकि सीहोर जिले में तेज बहाव के कारण कई बाइक बह गईं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में उफनते नाले के कारण एक मरीज को जेसीबी की बकेट में बैठाकर सुरक्षित पार कराया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बारिश से जीआरपी थाने के बाहर जलभराव की स्थिति बन गई। इस बीच मानसून ने सात दिन की देरी से राजस्थान तथा पांच दिन की देरी से दिल्ली में दस्तक दे दी है।

'बम-बम भोले' के जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रा शुरू, जम्मू से रवाना हुआ पहला जत्था; चारधाम में भी उमड़ा आस्था का सैलाब

24 न्यूज अपडेट

श्रीनगर/ देहरादून। बाबा बर्फानी के दर्शन का इंतजार गुरुवार को खत्म हो गया। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को विदा किया। 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। इस वर्ष 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त (रक्षाबंधन) तक जारी रहेगी। श्रद्धालु पारंपरिक पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। प्रशासन ने पहले जत्थे में केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को शामिल किया, जिन्होंने पूर्व पंजीकरण कराया था, आरएफआईडी कार्ड प्राप्त किया था और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की थी। अब तक करीब चार लाख श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। यात्रा को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित संवेदनशील क्षेत्रों में सेना, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। जगह-जगह वाहनों की जांच, पैदल गश्त और निगरानी बढ़ाई गई है। जम्मू में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) भी सक्रिय कर दिया गया है, जहां से पूरी यात्रा पर नजर रखी जा रही है। यात्रा शुरू होने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बेस कैंप का दौरा कर सुरक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, ठहरने और हेल्प डेस्क जैसी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं से सुरक्षित और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा करने की अपील की। इधर, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में भी श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 14.5 लाख से अधिक और केदारनाथ धाम में 13.75 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जून के तीसरे सप्ताह से बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है और अब दर्शनार्थियों के मामले में बद्रीनाथ ने केदारनाथ को पीछे छोड़ दिया है।

राम मंदिर चंदा कांड: CCTV को चकमा, शौचालय में छिपती थी नकदी; 79.85 लाख कैश के साथ 8 आरोपी जेल

24 न्यूज अपडेट

अयोध्या। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन के मामले में पुलिस जांच ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने मंदिर परिसर के भीतर ही चोरी की रकम छिपाने और सीसीटीवी कैमरों को धोखा देने का ऐसा तरीका अपनाया था, जिससे लंबे समय तक किसी को भनक नहीं लगी। पुलिस अब तक 79.85 लाख रुपये नकद, 1,121 अमेरिकी डॉलर और सोने-चांदी के आभूषण बरामद कर चुकी है। मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

शौचालय बना 'सेफ हाउस', मौका मिलते ही बाहर निकालते थे रकम

पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला ने बताया कि चोरी के बाद नकदी को तुरंत बाहर नहीं ले जाया जाता था। शक से बचने के लिए नोटों की गड्डियां पहले मंदिर परिसर के शौचालय में छिपा दी जाती थीं। बाद में सुरक्षा व्यवस्था ढीली होने या मौका मिलने पर थोड़ी-थोड़ी रकम बाहर निकाली जाती थी। पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम और इससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

CCTV के सामने बनती थी 'इंसानी दीवार'

जांच में यह भी सामने आया कि चोरी कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि पूरी योजना के तहत अंजाम दी जाती थी। आरोपियों ने नोट गिनने वाले कक्ष, कैमरों की लोकेशन और कर्मचारियों की दिनचर्या का पहले से अध्ययन किया था। जब एक व्यक्ति नकदी निकालता था, तब अन्य आरोपी उसके चारों ओर खड़े होकर कैमरे की नजर रोक देते थे। इस तरह 'ह्यूमन शील्ड' बनाकर कथित चोरी को अंजाम दिया जाता था।

कमरे की चाबी भी जांच के दायरे में

पुलिस के अनुसार, नोट गिनने वाले कक्ष की दो चाबियां थीं। एक बैंक अधिकारियों के पास होनी चाहिए थी, जबकि दूसरी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास थी। जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि कैश प्रबंधन से सीधे जुड़े नहीं होने के बावजूद टिन्नू के पास चाबी कैसे पहुंची।

जमीन, हॉस्टल और मकानों में लगाया गया पैसा

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कथित तौर पर चोरी की रकम का इस्तेमाल जमीन खरीदने, हॉस्टल निर्माण और अन्य संपत्तियां बनाने में किया गया। पुलिस आरोपियों के बैंक खातों, संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है ताकि आय से अधिक संपत्ति के पहलू की भी पड़ताल की जा सके।

मुख्य आरोपी से सबसे बड़ी बरामदगी

पुलिस ने मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से 20.39 लाख रुपये नकद, 1,121 अमेरिकी डॉलर, दो सोने की चेन, एक अंगूठी और चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। इसके अलावा करुणेश पांडेय से 18.07 लाख रुपये, अनुकल्प मिश्रा से 16.82 लाख रुपये, लवकुश मिश्रा से 14.25 लाख रुपये, रमाशंकर मिश्रा से 7.32 लाख रुपये, मनीष यादव से 2 लाख रुपये तथा रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू से 1 लाख रुपये नकद जब्त किया गया है।

खामेनेई को अंतिम विदाई में विशेष बुलावे पर महबूबा मुफ्ती तेहरान रवाना

24 न्यूज अपडेट

तेहरान/ नई दिल्ली। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार ने वैश्विक कूटनीति का केंद्र बना लिया है। 3 से 6 जुलाई तक तेहरान में आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि समारोह में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को ईरान ने भारत की विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है।

आमंत्रण स्वीकार करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह उनके लिए जीवन का एक दुर्लभ और सम्मानजनक अवसर है। उन्होंने कहा कि खामेनेई को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वह तेहरान जाएंगी।

भारत से केवल महबूबा मुफ्ती ही नहीं, बल्कि जैन संत आचार्य लोकेश मुनि, विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्गेरिटा तथा बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन भी अंतिम संस्कार समारोह में भाग लेंगे। इससे स्पष्ट है कि भारत की ओर से राजनीतिक, आध्यात्मिक और राजनयिक स्तर पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।

ईरानी प्रशासन के अनुसार अंतिम यात्रा में डेढ़ से दो करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो यह ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा राजकीय अंतिम संस्कार माना जाएगा। लगभग 30 देशों के प्रतिनिधिमंडलों के आगमन को देखते हुए तेहरान में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ग्रैंड मोसल्ला परिसर में अंतिम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां लाखों लोगों की मौजूदगी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा।

इस बीच ईरान में खामेनेई के परिवार के पांच सदस्यों के ताबूत भी अंतिम संस्कार की औपचारिकताओं के तहत एक साथ रखे गए हैं। अंतिम संस्कार की रस्में कई दिनों तक चलेंगी और देशभर में शोक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

उधर, अंतिम संस्कार के बीच पश्चिम एशिया की राजनीतिक हलचल भी जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ता सही दिशा में बढ़ रही है। वहीं कतर ने पुष्टि की है कि दोहा में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता के बाद अमेरिका और ईरान ने अंतिम संस्कार संपन्न होने के पश्चात बातचीत का अगला दौर शुरू करने पर सहमति जताई है। ईरान ने यह भी घोषणा की है कि अमेरिका-ईरान समझौते के तहत जारी होने वाले 6 अरब डॉलर के फ्रीज फंड का उपयोग आवश्यक वस्तुओं की खरीद में किया जाएगा। हालांकि तेहरान ने अमेरिका पर समझौते की कुछ शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए निगरानी समिति गठित करने का निर्णय भी लिया है।

दूसरी ओर, क्षेत्रीय तनाव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इजराइल ने स्पष्ट किया है कि उसकी सेना फिलहाल लेबनान, सीरिया और गाजा से नहीं हटेगी। वहीं ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को अपनी संप्रभुता का हिस्सा बताते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का कड़ा जवाब दिया जाएगा।

हालांकि समुद्री निगरानी एजेंसियों के अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य से व्यापारिक और तेल वाहक जहाजों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य होने लगी है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार को कुछ राहत मिली है। इसके बावजूद विशेषज्ञ मान रहे हैं कि हालिया संघर्ष ने दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और सामरिक रणनीतियों पर दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ा है।

खामेनेई की अंतिम विदाई केवल एक राजकीय समारोह नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया की बदलती भू-राजनीति, वैश्विक कूटनीति और अमेरिका-ईरान संबंधों की आगामी दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण अवसर भी बन गई है।

जयपुर नगर निगम के मैरिज ऑफिस में एसीबी का ट्रैप, मैरिज रजिस्ट्रार व कर्मचारी 12,500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

24 न्यूज अपडेट

जयपुर, 2 जुलाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार शाम जयपुर नगर निगम के लालकोठी स्थित मैरिज रजिस्ट्रेशन कार्यालय में बड़ी कार्रवाई करते हुए मैरिज रजिस्ट्रार और उसके कर्मचारी को 12,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई एसीबी की कोटा इकाई ने की। आरोपियों पर विवाह पंजीयन के लिए निर्धारित सरकारी शुल्क के अतिरिक्त प्रति आवेदन 2,500 से 3,000 रुपए तक की अवैध वसूली करने का आरोप है।

एसीबी के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि कोटा एसीबी को एक परिवादी ने शिकायत दी थी। परिवादी जयपुर के प्रताप नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में प्रधान के रूप में कार्यरत है, जहां गरीब एवं दहेज रहित विवाह संपन्न कराए जाते हैं। इन विवाहों का पंजीयन नगर निगम के लालकोठी स्थित मैरिज रजिस्ट्रेशन कार्यालय में कराया जाता है।

शिकायत के अनुसार, विवाह पंजीयन का निर्धारित शासकीय शुल्क मात्र 110 रुपए होने के बावजूद मैरिज रजिस्ट्रार विक्रम सिंह और कर्मचारी राकेश चौधरी प्रत्येक विवाह पंजीयन के लिए 2,500 से 3,000 रुपए तक रिश्वत की मांग करते थे। रिश्वत नहीं देने पर आवेदनकर्ताओं के दस्तावेजों में अनावश्यक कमियां बताकर उन्हें परेशान किया जाता था और पंजीयन प्रक्रिया में बाधा डाली जाती थी।

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का गोपनीय सत्यापन कराया। जांच में यह पुष्टि हुई कि मैरिज रजिस्ट्रार विक्रम सिंह अपने कर्मचारी राकेश चौधरी के माध्यम से रिश्वत की मांग करवा रहा था। सत्यापन के बाद गुरुवार को एसीबी की टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए नगर निगम कार्यालय में दोनों आरोपियों को 12,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

कार्रवाई के दौरान कर्मचारी राकेश चौधरी की तलाशी में 38 हजार रुपए अतिरिक्त नकद भी बरामद हुए, जिसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। एसीबी ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही उनके कार्यालय, निवास और अन्य संभावित ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई भी जारी है। ब्यूरो अब यह भी जांच कर रहा है कि रिश्वतखोरी का यह नेटवर्क कितना व्यापक था और इसमें अन्य लोगों की भी भूमिका थी या नहीं।

संपादकीय : मुश्किलों के बीच

पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त होने को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था के फिर से रफ्तार पकड़ने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर में गिरावट और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ अब देश में विनिर्माण गतिविधियों की वृद्धि भी धीमी पड़ गई है। एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, विनिर्माण में वृद्धि का आंकड़ा इस वर्ष मई के 55.0 से घटकर जून में 54.2 पर पहुंच गया। यही नहीं, नई कारोबारी मांग और अंतरराष्ट्रीय बिक्री की वृद्धि दर सुस्त रहने से वस्तुओं की खरीद, रोजगार सृजन और उत्पादन की रफ्तार भी कम हो गई है। यानी कुछ उपक्रमों को छोड़ दिया जाए, तो देश के ज्यादातर क्षेत्रों की वृद्धि में गिरावट देखी जा रही है, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। हालांकि, महंगाई से राहत दिलाने के लिए तेल कंपनियों ने बुधवार को वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में प्रति 19 किलोग्राम सिलेंडर पर 183.50 रुपए और विमान ईंधन में पांच रुपए प्रति लीटर की कटौती की है, लेकिन पिछले दिनों बढ़ाए गए दामों के मुकाबले यह राहत बेहद कम है। इसमें दोराय नहीं कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजे संकट का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय था, लेकिन सवाल यह है कि सरकार की ओर से इसके प्रभाव को कम करने के लिए समय रहते वैकल्पिक उपाय तलाशने पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया ? ऐसा भी नहीं है कि सरकार इस संकट की संभावनाओं से अनभिज्ञ थी। दावे किए जाते रहे कि स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, मगर इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम धरातल पर कहीं नजर नहीं आते हैं। एचएसबीसी की मासिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्ष जून में भारतीय वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय मांग में वृद्धि की रफ्तार 39 महीनों में सबसे कमजोर रही। इससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि भारतीय निर्यात कारोबार पर कितना गहरा असर पड़ा है। सर्वेक्षण में कई कंपनियों ने माना है कि उन्हें हाल के दिनों में नई नियुक्तियां रोकनी पड़ीं या उन्हें कम कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि लोगों को रोजगार के मोर्चे पर भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मांग और बाजार की स्थिति को लेकर चिंता के कारण जून में निवेशकों और कारोबारियों का भरोसा भी कमजोर पड़ा है। खासकर विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार को लेकर रुख असमंजस भरा रहा है, जिस कारण विदेशी निवेश की निकासी का सिलसिला जारी है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य होने को लेकर भी भरोसा घट रहा है। यही वजह है कि अगले एक वर्ष में उत्पादन बढ़ने का अनुमान लगाने वाली कंपनियों का अनुपात इस वर्ष मई की तुलना में जून में आधा रह गया है। वहीं, तेल कंपनियों ने पश्चिम एशिया में संघर्ष से कीमतों में आई तेजी के बाद वाणिज्यिक एलपीजी और विमान ईंधन के दामों में पहली बार कटौती की है। मगर सवाल है कि क्या महंगाई से यह राहत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस के दामों में आई कमी के सामान अनुपात में है ? अक्सर यह देखा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें चढ़ने का हवाला देकर देश में ईंधन के दामों में बढ़ोतरी कर दी जाती है, लेकिन जब वैश्विक बाजार में कीमतें कम होती हैं, तो उनका पूरा लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाता है।

भ्रष्टाचार की दीमक

भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है, जो किसी भी देश की प्रगति, अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों को अंदर से खोखला कर देती है । व्यवस्था में यह रोग न केवल आम जनता के विश्वास को तोड़ता है, बल्कि विकास के अवसरों को सीमित कर समाज में असमानता की खाई को और गहरा कर देता है। देश में राजनीतिक दल चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने का भरोसा दिलाते हैं, मगर सत्ता में आने के बाद उनकी नाक के नीचे करोड़ों रुपए के घोटालों की जमीन तैयार हो जाती है। इसका ताजा उदाहरण हरियाणा में करीब पांच सौ करोड़ रुपए का वह घोटाला है, जिसमें संलिप्तता के आरोप में बीते मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक वरिष्ठ आइएएस अधिकारी को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन गिरफ्तार किया है । जाहिर है कि यह वित्तीय हेराफेरी एक-दो दिन या या फिर सप्ताह भर में तो नहीं हुई होगी, ऐसे में सवाल है कि शासन-प्रशासन में उच्च पदों पर बैठे लोगों और सतर्कता एजेंसियों को इसकी भनक पहले क्यों नहीं लगी? देश में वित्तीय गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाए गए हैं, इसके बावजूद अगर भ्रष्टाचार का सिलसिला थम नहीं रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सरकारी विभागों में कई ऐसे मामले होते हैं, जो कभी पकड़ में ही नहीं आते हैं या फिर उन्हें जानबूझकर दबा दिया जाता है। जो मामले सामने आते हैं, उनमें भी ज्यादातर का खुलासा तब होता है, जब करोड़ों रुपए इधर से उधर कर दिए जाते हैं। हरियाणा में आइडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में भी यही हुआ गिरफ्तार किए गए वरिष्ठ आइएएस अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रहते हुए करीब 169 करोड़ रुपए का गबन किया है। इस मामले में दो बैंक अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पता चलता है कि वित्तीय हेराफेरी को अंजाम देने के लिए साठगांठ के जरिए किस तरह एक तंत्र खड़ा कर दिया जाता है। जांच में सामने आया है कि संबंधित महकमे के जो करोड़ों रुपए बैंक खाते में भेजे गए, बाद में उन्हें फर्जी तरीके से निकाल लिया गया। इससे स्पष्ट है कि सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही का किस कदर अभाव है।

38 दिन से ठप मानवता की रसोई:

एमबी अस्पताल में रोज 600 जरूरतमंदों की थाली छिनी, प्रशासन के आश्वासन अब भी अधूरे

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराणा भूपाल चिकित्सालय (एमबी हॉस्पिटल) में पिछले आठ वर्षों से गरीब मरीजों और उनके परिजनों की भूख मिटाने वाली निःशुल्क भोजनशाला पिछले 38 दिनों से बंद पड़ी है। 25 मई को शॉर्ट सर्किट के कारण गैस सिलेंडर में आग लगने की मामूली घटना के बाद सुरक्षा कारणों से भोजनशाला पर ताला लगा दिया गया था। तब से प्रतिदिन सैकड़ों जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजनों को भोजन के लिए अस्पताल परिसर से बाहर भटकना पड़ रहा है, जबकि भोजनशाला में रखा राशन और खाद्य सामग्री भी खराब होने की कगार पर पहुंच गई है। भोजनशाला संचालित करने वाले संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि यहां प्रतिदिन करीब 600 लोगों को दोनों समय निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता था। मरीजों के लिए पौष्टिक दलिया की भी व्यवस्था रहती थी। इस सेवा का लाभ दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से इलाज के लिए आने वाले गरीब मरीजों, उनके परिजनों, वृद्धजनों, मजदूर वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलता था। अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ रहने वाले परिजनों पर पहले ही दवाइयों, जांच, यात्रा और ठहरने का आर्थिक बोझ रहता है। ऐसे में यह भोजनशाला उनके लिए सबसे बड़ा सहारा थी।

बाहर खाना खरीदने की मजबूरी, कई परिवार एक समय भोजन पर निर्भर

भोजनशाला बंद होने के बाद जरूरतमंद परिवारों को मजबूरी में बाहर होटलों, ढाबों और ठेलों पर पैसे खर्च कर भोजन करना पड़ रहा है।

आर्थिक रूप से कमजोर कई परिवार एक समय का भोजन कर दिन गुजारने को विवश हैं। सुबह से देर शाम तक अस्पताल में मरीजों की सेवा में लगे परिजनों के सामने भोजन की व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या बन गई है।

प्रशासन से कई बार गुहार, समाधान अब तक नहीं

संस्थान के अनुसार घटना के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन ने भोजनशाला को सील कर दिया था। इसके बाद से संस्थान ने कई बार अस्पताल प्रशासन से वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि सेवा बाधित न हो, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इस बीच भोजनशाला में रखा राशन, खाद्य सामग्री और अन्य सामान लंबे समय तक बंद रहने के कारण खराब होने लगा है।

जनप्रतिनिधियों तक पहुंची बात, फिर भी नहीं निकला रास्ता

भोजनशाला को दोबारा शुरू कराने के लिए संस्थान के पदाधिकारियों ने शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा तथा जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल को भी स्थिति से अवगत कराया है। संस्थान का कहना है कि अस्पताल प्रशासन यदि वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करा दे तो सेवा तुरंत पुनः शुरू की जा सकती है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई निर्णय नहीं हुआ है।

केवल भोजन नहीं, मानव सेवा का अभियान

संस्थान से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह केवल भोजन वितरण नहीं बल्कि मानव सेवा का निरंतर चलने वाला अभियान है। पिछले आठ वर्षों में इस भोजनशाला ने हजारों गरीब और जरूरतमंद मरीजों व उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया है। यहां किसी की जाति, धर्म, क्षेत्र या पहचान नहीं पूछी जाती, केवल उसकी जरूरत देखी जाती है। यही कारण है कि आज भी अनेक लोग भोजनशाला के बाहर पहुंचकर पूछते हैं कि सेवा दोबारा कब शुरू होगी।

रोज खाली रह रही हैं 600 थालियां

जिस रसोई से प्रतिदिन लगभग 600 लोगों के लिए भोजन तैयार होता था, वहां पिछले 38 दिनों से ताला लटका हुआ है। इस अवधि में हजारों जरूरतमंद भोजन से वंचित रह चुके हैं। सबसे अधिक प्रभावित वे परिवार हैं जो सीमित आय के बावजूद गांवों से इलाज के लिए उदयपुर आते हैं और जिनके लिए यह भोजनशाला दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण सहारा थी।

भूख इंतजार नहीं करती

अस्पताल में भर्ती मरीज की पीड़ा जितनी बड़ी होती है, उससे कम चिंता उसके परिजनों की नहीं होती। इलाज, दवाइयों और जांचों के बीच कई परिवारों के पास भोजन खरीदने तक के पैसे नहीं बचते। ऐसे समय यह निःशुल्क भोजनशाला केवल भोजन नहीं परोसती, बल्कि यह भरोसा भी देती है कि संकट की घड़ी में समाज उनके साथ खड़ा है। पिछले 38 दिनों से यह सहारा बंद होने से प्रतिदिन सैकड़ों परिवार प्रभावित हो रहे हैं।

30 वर्षों तक एक ही विद्यालय में शिक्षा की अलख जगाते रहे शिक्षक सतीश जैन, बिना तबादले और पदोन्नति के यहीं से हुए सेवानिवृत्त

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। समर्पण, सेवा और कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण पेश करते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षक सतीश जैन ने अपने शिक्षकीय जीवन के पूरे 30 वर्ष लगभग एक ही विद्यालय को समर्पित कर दिए। उनका पहला पदस्थापन 13 जुलाई 1996 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जोधपुरिया (कुराबड़) में हुआ था और उल्लेखनीय बात यह रही कि सेवानिवृत्ति भी उन्होंने इसी विद्यालय से प्राप्त की। शहर उदयपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित इस दुर्गम विद्यालय में जब उनका पदस्थापन हुआ, तब वहां आने-जाने के लिए समुचित सड़क सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से समझौता नहीं किया और निरंतर विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में जुटे रहे। विशेष बात यह भी रही कि लंबे सेवाकाल के दौरान उनकी न तो पदोन्नति हुई और न ही उन्होंने स्थानांतरण के लिए प्रयास किया, जबकि वे शिक्षक संगठन से भी जुड़े रहे। इसके बावजूद उन्होंने अपने विद्यालय और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए पूरी निष्ठा के साथ सेवा देना ही अपना धर्म माना। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की ज्योति जलाने वाले सतीश जैन का यह शिक्षकीय सफर इस बात का प्रेरक उदाहरण है कि सच्चा शिक्षक पद, प्रतिष्ठा या स्थान से नहीं, बल्कि अपने समर्पण, कर्म और विद्यार्थियों के प्रति जिम्मेदारी से पहचाना जाता है। तीन दशकों तक एक ही विद्यालय में सेवाएं देकर उन्होंने शिक्षा जगत में कर्तव्यपरायणता और सेवा भावना की मिसाल कायम की।

रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर मीरा ने किया 11 चिकित्सकों का सम्मान

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 2 जुलाई। विश्व डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर मीरा की ओर से चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं अग्रणी सेवाएं प्रदान करने वाले 11 चिकित्सकों का सम्मान किया गया। क्लब अध्यक्ष रोटेरियन कुकू लिखारी ने बताया कि समाज के प्रति समर्पित सेवाएं देने वाले चिकित्सकों का उपरणा ओढ़ाकर, तिलक लगाकर एवं पौधा भेंट कर अभिनंदन किया गया। सम्मानित चिकित्सकों में पारस हॉस्पिटल के डॉ. देवेन्द्र सरीन, महाराणा भोपाल हॉस्पिटल के डॉ. मनस्विन सरीन, अमेरिका से आईं डॉ. निष्ठा, डॉ. अभिषेक, डॉ. सृष्टि, डॉ. नितिन, सरगम हॉस्पिटल के डॉ. सी.पी. पुरोहित, डॉ. सनाढ्या, डॉ. भट्ट, डॉ. हर्ष जैन तथा डॉ. भानु एवं मुकेश देवपुरा सहित अन्य चिकित्सकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सहायक प्रांतपाल (असिस्टेंट गवर्नर) रोटेरियन संगीता मुंदड़ा, सचिव स्नेहा के. शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीरा मजूमदार, राजकुमारी गांधी, अर्चना व्यास, कविता श्रीवास्तव, नीलम दुबे सहित क्लब के अनेक सदस्य उपस्थित रहे।

प्रो. नीरज शर्मा बने स्ववित्त पोषित सलाहकार मंडल के सदस्य सचिव, कर्मचारी संगठन ने किया सम्मान

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 2 जुलाई। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रो. नीरज शर्मा को स्ववित्त पोषित सलाहकार मंडल (एसएफएबी) का सदस्य सचिव नियुक्त किए जाने पर गुरुवार को विश्वविद्यालय कर्मचारी संगठन (भारतीय मजदूर संघ) की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष नारायणलाल सालवी के नेतृत्व में आयोजित सम्मान समारोह में प्रो. शर्मा का उपरणा ओढ़ाकर स्वागत किया गया तथा नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर संगठन के सदस्य यूनुस खान, सत्य प्रकाश शर्मा, भावना चौधरी, साधना मेहता, अलका अग्रवाल, किरण तंवर सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रो. नीरज शर्मा अपने अनुभव और कार्यशैली से नई जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के विकास एवं संचालन को नई दिशा देंगे।

समाचार भेजने के लिए हमारी मेल आई-डी पर संपर्क करें -
desk24newsupdate@gmail.com
wathsapp : 8852073787

प्रेम प्रसंग के चलते अपहरण के बाद हत्या मामला: सुखेर पुलिस की बड़ी सफलता, 8 और आरोपी गिरफ्तार, एक बाल अपचारी डिटेन; अब तक 11 आरोपी पुलिस गिरफ्त में

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 2 जुलाई। उदयपुर जिले के सुखेर थाना पुलिस ने बहुचर्चित हिम्मत सिंह सोलंकी अपहरण एवं हत्या प्रकरण में बड़ी सफलता हासिल करते हुए आठ और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बाल अपचारी को डिटेन किया गया है। इससे पहले पुलिस इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की पिकअप भी बरामद कर चुकी थी। ताजा कार्रवाई के बाद अब तक इस मामले में कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार अथवा डिटेन किया जा चुका है। पुलिस पूरे घटनाक्रम में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका और हत्या की साजिश के विभिन्न पहलुओं की भी गहन जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, प्रकरण की रिपोर्ट मावली क्षेत्र के भीमल (वागननाडा) निवासी सुरेन्द्र सिंह कितावत ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उनके जीजाजी हिम्मत सिंह सोलंकी (पिता मोकम सिंह सोलंकी), निवासी बॉडी चिरवा, मारुवास (मावली), 22 जून 2026 को शाम करीब 7:30 बजे अपनी कार (आरजे-27-सीएन-9701) से कैलाशपुरी स्थित फुटिया घाटी (राया माता क्षेत्र) में एक महिला से मिलने पहुंचे थे। वह नर्सरी के पास अपनी कार में महिला का इंतजार कर रहे थे, तभी तेज गति से आई बिना नंबर की सफेद पिकअप ने उनकी कार को टक्कर मार दी। शिकायत के अनुसार, पिकअप से 8 से 10 लोग नीचे उतरे और हिम्मत सिंह की कार पर पत्थरों एवं लाठियों से हमला कर उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने हिम्मत सिंह के साथ बेरहमी से मारपीट की और उन्हें जबरन पिकअप में डालकर अपने साथ ले गए। बाद में इस घटना ने हत्या का रूप ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण और हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हिम्मत सिंह का पिछले करीब एक वर्ष से एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी संबंध को लेकर महिला के पति छगन, ससुर टेका तथा उसके भाई सहित अन्य लोगों के साथ हिम्मत सिंह की रंजिश थी। पुलिस इसी एंगल को आधार बनाकर जांच कर रही है और मान रही है कि वारदात पूर्व नियोजित साजिश के तहत अंजाम दी गई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने मामले में शामिल सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश ओझा तथा पुलिस उपाधीक्षक (नगर पश्चिम) राजेश यादव के सुपरविजन में थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने लगातार मुखबिर तंत्र, तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन, संदिग्धों की गतिविधियों और अन्य सूचनाओं का विश्लेषण करते हुए विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर आठ और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में सुंदर (19) पुत्र उदयलाल, मदन (24) पुत्र बंशीलाल, डालचंद्र (18) पुत्र परथा, देवीलाल (19) पुत्र गोवर्धनलाल, सभी निवासी प्रतापपुरा थाना सुखेर; कमलेश (22) पुत्र शंकरलाल एवं रमेश (30) पुत्र डालुजी, दोनों निवासी गवरी चौक, अंबामाता; रुपलाल (29) पुत्र भोलीराम निवासी कलाओं की गवाड़ी, सुखेर तथा जितेन्द्र (19) पुत्र रामलाल निवासी मेहरो का गुड़ा, सुखेर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया गया है।

पुलिस के अनुसार, अब तक इस मामले में कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार या डिटेन किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर वारदात की साजिश, प्रत्येक आरोपी की भूमिका, हत्या के बाद किए गए घटनाक्रम तथा अन्य संभावित आरोपियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अनुसंधान अभी जारी है और आवश्यकता पड़ने पर अन्य संदिग्धों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई को सफल बनाने वाली टीम में थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक केसर सिंह, हरीश चन्द्र सनाढ्य एवं नारायण सिंह, हैड कांस्टेबल श्रवण और सुरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल अचला राम, शिम्भू राम, भारत सिंह, तरुण, सुमेरा राम, महिला कांस्टेबल रेखा, कांस्टेबल कपिल तथा साइबर सेल उदयपुर के लोकेश रायकवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस अधिकारियों ने टीम की त्वरित कार्रवाई, तकनीकी विश्लेषण और समन्वित प्रयासों की सराहना करते हुए इसे मामले के खुलासे में अहम बताया।

प्रोफेसर पर अश्लील संदेश और यौन संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप, युवती ने कॉलोनी में किया हंगामा

24 न्यूज अपडेट

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक शासकीय महाविद्यालय के प्रोफेसर पर पड़ोस में रहने वाली युवती ने अश्लील संदेश भेजने और यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। आरोपों से नाराज युवती अपने मंगेतर के साथ प्रोफेसर के आवास पहुंची, जहां दोनों के बीच तीखी कहासुनी हुई। इस दौरान युवती ने प्रोफेसर का कॉलर पकड़कर थप्पड़ मार दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार प्रोफेसर रेमन भार्गव शासकीय महाविद्यालय, कुंजारा में पदस्थ हैं और युवती उनके पड़ोस में रहती है। युवती का आरोप है कि पिछले करीब डेढ़ वर्ष से प्रोफेसर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से लगातार आपत्तिजनक संदेश भेज रहे थे तथा यौन संबंध बनाने का दबाव डाल रहे थे। विरोध करने के बावजूद कथित तौर पर फोन कॉल और संदेशों के जरिए परेशान किया जाता रहा। इन आरोपों से क्षुब्ध युवती एक जुलाई को अपने होने वाले पति के साथ प्रोफेसर के घर पहुंची। वहां विवाद बढ़ने पर उसने सार्वजनिक रूप से प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिए। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है। वीडियो में प्रोफेसर की पत्नी बीच-बचाव करते हुए और माफी मांगती हुई भी दिखाई दे रही हैं। युवती ने दावा किया कि वह अकेली पीड़ित नहीं है और प्रोफेसर ने अन्य लड़कियों को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। उसने ऐसी महिलाओं से सामने आने की अपील करते हुए कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह कानूनी लड़ाई जारी रखेगी।

घटना के संबंध में युवती ने लैलूंगा थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि थाना प्रभारी गिरधारी साव के अनुसार बाद में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया, जिसके बाद मामले में आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।

वहीं, शासकीय महाविद्यालय कुंजारा के प्राचार्य एम.एल. पटेल ने कहा कि यह घटना कॉलेज परिसर से बाहर की है और इसे दोनों पक्षों का निजी मामला माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रशासन को इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि शिकायत मिलती तो नियमानुसार उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाती।

रग रग में रिश्वत का दम : जयपुर नगर निगम का जमादार 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

24 न्यूज अपडेट

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को जयपुर नगर निगम में बड़ी कार्रवाई करते हुए पट्टा संबंधी कार्य के बदले रिश्वत लेने के आरोप में एक जमादार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जबकि उसने परिवादी से कुल 2 लाख रुपए की मांग की थी। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रामसिंह यादव (28), पुत्र मूलचंद यादव, सीकर जिले के श्रीमाधोपुर का निवासी है और जयपुर नगर निगम के हवामहल-आमेर जोन में पट्टा/ लीज शाखा में जमादार के पद पर कार्यरत है।

पट्टा जारी करने के बदले मांगी थी रिश्वत

परिवादी ने एसीबी को शिकायत देकर बताया था कि उसके पिता के नाम पट्टा जारी कराने का मामला लंबे समय से नगर निगम में लंबित है। कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद काम नहीं हो रहा था। आरोप है कि आरोपी जमादार ने फाइल आगे बढ़ाने और पट्टा जारी कराने के बदले 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी।

शिकायत सही मिलने पर बिछाया जाल

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने उसका सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर ट्रैप की योजना बनाई गई। गुरुवार को परिवादी को 50 हजार रुपए लेकर आरोपी के पास भेजा गया। जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की पहली किस्त स्वीकार की, पहले से तैनात एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि रिश्वत मांगने के मामले में कोई अन्य कर्मचारी या अधिकारी भी शामिल था या नहीं। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

आरएएस-2026 के लिए आवेदन का आखिरी मौका आज, 607 पदों पर भर्ती; प्रारंभिक परीक्षा अब 6 दिसंबर को होगी

24 न्यूज अपडेट

अजमेर, 2 जुलाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (RAS) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई है। इच्छुक अभ्यर्थी आज रात तक आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने इस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में भी बदलाव करते हुए इसे अब 6 दिसंबर 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया है, जबकि मुख्य परीक्षा 1 और 2 मई 2027 को प्रस्तावित है। आरएएस-2026 भर्ती के तहत कुल 607 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें 192 पद राज्य सेवाओं तथा 415 पद अधीनस्थ सेवाओं के हैं। आवेदन प्रक्रिया 4 जून से जारी है और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

राज्य सेवाओं में सबसे अधिक 57 पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS), 36 पद राजस्थान लेखा सेवा, 26 पद राजस्थान पुलिस सेवा, 12 पद राजस्थान उद्योग सेवा, 11 पद राजस्थान राज्य बीमा सेवा, 10 पद राजस्थान परिवहन सेवा तथा अन्य विभागों के विभिन्न पद शामिल हैं। वहीं अधीनस्थ सेवाओं में राजस्थान तहसीलदार सेवा के 148 पद (NSA व SA), राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा के 113 पद, राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा के 35 पद, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के 22 पद, राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा के 20 पद, खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के 19 पद सहित विभिन्न विभागों के कुल 415 पदों पर भर्ती की जाएगी।

भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया तीन चरणों'प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार'के माध्यम से पूरी होगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) होगी, जबकि मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव) स्वरूप में आयोजित की जाएगी। आवेदन शुल्क सामान्य एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर ओबीसी/ एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं राजस्थान के नॉन-क्रीमीलेयर ओबीसी, एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपए रखा गया है।

आरपीएससी की अन्य भर्तियों में भी आवेदन जारी

आरपीएससी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीपी) के 371 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन प्रक्रिया जारी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई निर्धारित है, जबकि प्रारंभिक परीक्षा 2 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। इस भर्ती में भी आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी तथा पात्र अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके अलावा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 3 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। टॉक्सिकोलॉजी, फिजिक्स और बैलिस्टिक्स डिवीजन में एक-एक पद के लिए अभ्यर्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की परीक्षा 13 से 17 अक्टूबर 2026 के बीच कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट (CBRT) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

राजसमंद में दिलाई थी डमी कैंडिडेट को वनरक्षक की परीक्षा, एसओजी ने फर्जीवाड़े का किया पर्दाफाश

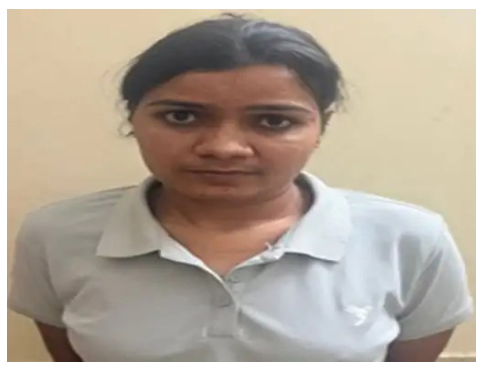

24 न्यूज अपडेट

जयपुर। प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बैठाकर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वनरक्षक भर्ती-2020 में फर्जीवाड़ा करने वाली एक महिला वनरक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने न केवल अपनी जगह दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाई, बल्कि पहले से दर्ज आपराधिक मामले को छिपाकर पुलिस सत्यापन के आधार पर सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी प्रमिला (29) जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र की निवासी है और वर्तमान में सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र स्थित जीरावल नाका पर वनरक्षक के पद पर कार्यरत थी। जांच में सामने आया कि वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020, जो वर्ष 2022 में आयोजित हुई थी, में प्रमिला का परीक्षा केंद्र राजसमंद के कांकरोली में था। आरोप है कि उसने स्वयं परीक्षा देने के बजाय अपनी जगह एक डमी कैंडिडेट को बैठाकर परीक्षा दिलवाई। इसी आधार पर उसका चयन वनरक्षक पद पर हो गया।

एसओजी ने वर्ष 2025 में दर्ज प्रकरण की जांच के दौरान दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि इस पूरे खेल में और कौन-कौन लोग शामिल थे। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि प्रमिला का नाम पहले भी रीट-2021 परीक्षा में डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा दिलाने के प्रयास में सामने आ चुका है। उस समय जयपुर के सिंधी कैंप थाना पुलिस ने परीक्षा शुरू होने से पहले ही मुख्य अभ्यर्थी और डमी कैंडिडेट दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे रीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा सफल नहीं हो सका। इसके बावजूद आरोपी ने वनरक्षक पद पर नियुक्ति के समय अपने खिलाफ दर्ज इस आपराधिक मामले की जानकारी छिपा ली। आरोप है कि पुलिस सत्यापन के दौरान भी उसने तथ्य छिपाकर क्लीन रिपोर्ट हासिल की और सरकारी सेवा में शामिल हो गई। एसओजी अब इस बात की भी जांच कर रही है कि पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में लापरवाही हुई या किसी स्तर पर मिलीभगत के चलते आरोपी को नियुक्ति मिल गई। मामले में आगे और गिरफ्तारियों की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है।

सरिस्का में प्रकृति का अनोखा करिश्मा: पहली बार दिखे सफेद मोर और 'गोल्डन सांभर', बाघों की संख्या पहुंची 56

24 न्यूज अपडेट

अलवर, 2 जुलाई। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में इन दिनों प्रकृति का अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। प्रदेश के इस प्रमुख वन क्षेत्र में पहली बार एक दुर्लभ सफेद मोर और धूप में सोने की तरह चमकने वाला 'गोल्डन सांभर' दिखाई दिया है। वन्यजीव विशेषज्ञ इसे आनुवंशिक परिवर्तन (जेनेटिक म्यूटेशन) का परिणाम मान रहे हैं। इन दुर्लभ जीवों की मौजूदगी ने सरिस्का की जैव विविधता को नई पहचान दी है, वहीं बाघों की लगातार बढ़ती संख्या ने इसे देश के सबसे सफल टाइगर संरक्षण मॉडलों में शामिल कर दिया है।

सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन स्थित बाला किला और गंगोडी क्षेत्र में जून के पहले सप्ताह के दौरान दूधिया सफेद रंग का मोर देखा गया। सबसे पहले इसकी जानकारी जंगल में गश्त कर रहे वनकर्मियों को मिली, लेकिन तस्वीर नहीं ली जा सकी। बाद में ओडिशा के एक वन्यजीव फोटोग्राफर ने इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद कीं। यह क्षेत्र बाघिन एसटी-19 और अन्य बाघों का भी प्रमुख आवास है, जिससे अब पर्यटकों को बाघों के साथ इस दुर्लभ मोर के भी दर्शन होने की संभावना बढ़ गई है। इसी बीच सरिस्का में एक 'गोल्डन सांभर' भी देखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, सामने से देखने पर धूप में उसका शरीर सुनहरी आभा बिखेरता दिखाई देता है। टाइगर विशेषज्ञ निरंजन सिंह के मुताबिक सफेद मोर और गोल्डन सांभर जैसे दुर्लभ रंग वाले वन्यजीवों का दिखना अत्यंत असामान्य घटना है। उन्होंने बताया कि यह बदलाव शरीर में पिगमेंटेशन या हार्मोन संबंधी आनुवंशिक परिवर्तन के कारण हो सकता है।

दुर्लभ वन्यजीवों की मौजूदगी के साथ-साथ सरिस्का बाघ संरक्षण के क्षेत्र में भी नई मिसाल कायम कर रहा है। करीब 18 वर्ष पहले पूरी तरह बाघविहीन हो चुके इस रिजर्व में अब बाघों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। संरक्षण की इस उल्लेखनीय सफलता का अध्ययन करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के वन विभागों के अधिकारी इन दिनों सरिस्का पहुंच रहे हैं।

7 दिन की देरी के बाद मेहरबान हुआ मानसून, राजस्थान में दस्तक, उदयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर शुरू

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। तपती गर्मी और उमस से जूझ रहे राजस्थान के लिए आखिरकार राहत की खबर आ गई। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने गुरुवार को सामान्य समय से करीब एक सप्ताह की देरी के बाद प्रदेश में प्रवेश कर लिया। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की सक्रियता अब तेजी से बढ़ेगी और अगले दो से तीन दिनों में इसका विस्तार पूरे राजस्थान में होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार फिलहाल मानसून की उत्तरी सीमा टोंक, जयपुर और अलवर से होकर गुजर रही है। अनुकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण यह जल्द ही पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान की ओर तेजी से बढ़ेगा। लंबे इंतजार के बाद मानसून की आमद से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं भीषण गर्मी से परेशान लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने गुरुवार को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। विशेष रूप से कोटा संभाग के कुछ इलाकों में अतिभारी बारिश होने का भी पूर्वानुमान है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां लगातार सक्रिय रहेंगी। पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश दर्ज की जा सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी जल्द बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है। जोधपुर और बीकानेर संभाग में अंधड़ और बारिश की गतिविधियां तेज होने के संकेत हैं, जिससे रेगिस्तानी इलाकों को भी राहत मिलेगी। इस बार मानसून ने 2 जुलाई को राजस्थान में प्रवेश किया है, जो सामान्य तिथि से लगभग सात दिन देर है। पिछले एक दशक में इससे पहले 2019 में भी मानसून ने इसी तारीख को प्रदेश में दस्तक दी थी। वहीं 2025 में मानसून 18 जून को पहुंच गया था, जबकि 2017 में इसकी सबसे जल्दी एंट्री 15 जून को दर्ज की गई थी। मौसम विभाग का मानना है कि यदि वर्तमान परिस्थितियां बनी रहीं तो जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून पूरे राजस्थान को अपने आगोश में ले लेगा और प्रदेश में खरीफ फसलों की बुवाई के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो जाएगा।

एसपी कार्यालय में बदली व्यवस्था, अब नहीं चढ़नी होंगी सीढ़ियां, बुजुर्ग का वीडियो वायरल होने के बाद फैसला

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर में एक बुजुर्ग महिला का एसपी कार्यालय की पहली मंजिल तक घिसट-घिसटकर पहुंचने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। मामला सामने आते ही जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने इस पर अपना पक्ष रखा और नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की। एसपी अमृता दुहन ने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि संबंधित बुजुर्ग महिला कब और किस उद्देश्य से कार्यालय आई थीं। उनकी महिला से मुलाकात भी नहीं हुई। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यालय में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों और विशेष योग्यजनों की सुविधा पुलिस की प्राथमिकता है। घटना के बाद अब एसपी कार्यालय में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत कार्यालय के भूतल पर विशेष प्रतीक्षा और बैठक क्षेत्र बनाया गया है, ताकि उन्हें पहली मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता न पड़े। नई व्यवस्था के अनुसार यदि बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति के साथ कोई परिजन है तो वह उनकी ओर से आवेदन संबंधित अधिकारी तक पहुंचाएगा। वहीं, यदि कोई परिवादी अकेले कार्यालय पहुंचता है तो भूतल पर तैनात पुलिसकर्मी स्वयं उसका आवेदन संबंधित शाखा तक पहुंचाएंगे और पूरी प्रक्रिया में आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराएंगे। एसपी का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, समावेशी और आमजन के लिए सुगम बनाना है, ताकि किसी भी वरिष्ठ नागरिक या विशेष योग्यजन को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल यह व्यवस्था वैकल्पिक रूप से शुरू की गई है, जिसे जल्द ही स्थायी रूप दिया जाएगा। यानी जिस घटना ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, उसके बाद अब उदयपुर पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए नई पहल शुरू कर दी है।

वल्लभनगर से 'VB G RAM G' अभियान का आगाज, गांव-गांव पहुंचेंगी केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 01 जुलाई। राष्ट्रीय तीर्थ प्रताप गौरव केंद्र में 12 जुलाई को आयोजित होने वाले विप्र प्रतिभा सम्मान समारोह एवं प्रशासनिक सेवा परीक्षा मार्गदर्शन सेमिनार के आमंत्रण पत्र का गरिमामय विमोचन किया गया। विमोचन विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षा, रोजगार एवं प्रतियोगी परीक्षा प्रकोष्ठ डॉ. एच. आर. दवे तथा आयोजन समिति के समन्वयकगणों द्वारा संपन्न किया गया। इस अवसर पर डॉ. दवे ने उक्त आयोजन को विप्र समाज की शैक्षणिक उत्कृष्टता, बौद्धिक जागृति एवं प्रशासनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी उपक्रम बताते हुए समाज के प्रबुद्धजनों, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों एवं युवाओं से अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा, व्यवस्थाओं एवं उद्देश्यों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करते हुए इसे समाज की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत, मार्गदर्शक एवं व्यक्तित्व-विकास का सशक्त मंच बताया गया। बैठक में उपस्थित समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने समस्त विप्र समाजजन से आग्रह किया कि प्रतिभा सम्मान हेतु जारी ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र (गूगल फॉर्म) को आवश्यक दस्तावेजों सहित यथाशीघ्र पूर्ण कर प्रेषित करें, जिससे 12 जुलाई को आयोजित होने वाले समारोह हेतु सम्मानित की जाने वाली प्रतिभाओं का सुव्यवस्थित चयन, सूचीकरण एवं समस्त व्यवस्थाओं का समयबद्ध नियोजन सुनिश्चित किया जा सके। पात्र प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने तथा आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सभी पात्र प्रतिभागियों एवं अभिभावकों से निर्धारित तिथि से पूर्व पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करने का आग्रह किया गया। अंत में शिक्षा, रोजगार एवं प्रतियोगी परीक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव गणेश नागदा ने कार्यक्रम की सफलता हेतु समाज के समस्त पदाधिकारियों, प्रबुद्धजनों, दानदाताओं एवं विप्र बंधुओं से तन, मन एवं धन से सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समाज की प्रतिभाओं के सम्मान, युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन तथा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने वाला यह आयोजन विप्र समाज के लिए एक ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायी मील का पत्थर सिद्ध होगा। विमोचन समारोह में डॉ. भगवती शंकर व्यास, मधुसूदन पालीवाल, महेंद्र आमेटा, लोकेश पालीवाल, राजेश पालीवाल, दिनेश शुक्ला, दीप्ति मेनारिया, भूपेंद्र श्रीमाली, हेमंत आमेटा, नीरज नागदा, डॉ. मनीष श्रीमाली, डॉ. मनीष तिवारी सहित समाज के अनेक गणमान्य सदस्य एवं विप्र बंधु उपस्थित रहे।

सीमावर्ती धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई रोकने की मांग, नाजिया इलाही खान की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का ज्ञापन

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 2 जुलाई। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में धार्मिक स्थलों को हटाए जाने की कथित कार्रवाई और सोशल मीडिया पर वायरल कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने गुरुवार को राष्ट्रपति और जिला कलक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर केंद्र व राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। विभाग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही कथित विवादित टिप्पणियों के मामले में नाजिया इलाही खान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग उठाई। जिलाध्यक्ष मोहम्मद रईस खान के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित कुछ मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों को हटाए जाने की खबरों से स्थानीय लोगों और विभिन्न समुदायों में गहरा असंतोष व्याप्त है। ज्ञापन में दावा किया गया कि यदि इस प्रकार की कार्रवाई जारी रही तो सीमावर्ती क्षेत्रों का सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है, जिससे देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने सरकार से धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी पक्षों से संवाद स्थापित करने की मांग की। ज्ञापन में सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित वीडियो का भी उल्लेख किया गया, जिसमें नाजिया इलाही खान द्वारा पैगंबर मोहम्मद और हजरत आयशा के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करने के साथ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली हैं। ज्ञापन में प्रशासन से भारतीय कानून के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की गई। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग किसी धर्म, धार्मिक महापुरुष या समुदाय का अपमान करने अथवा समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए नहीं किया जा सकता। विभाग ने दावा किया कि संबंधित महिला के खिलाफ देश के विभिन्न शहरों में पहले भी प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कानून के शासन और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों का सरकार को अल्टीमेटम, 25 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन की उदयपुर जिला शाखा सहित प्रदेशभर के कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो 25 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। संगठन का कहना है कि विभाग में कार्यरत करीब 16 हजार मंत्रालयिक कर्मचारी वर्षों से सेवा संबंधी विसंगतियों और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। कई बार मांगें उठाने और ज्ञापन देने के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। संगठन ने आरोप लगाया कि वर्ष 2013 की भर्तियों की जांच के नाम पर कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हुए, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। अब कर्मचारी केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे और लिखित आदेशों के साथ ठोस कार्रवाई चाहते हैं।

आठ प्रमुख मांगें सरकार के सामने

संगठन ने सरकार के समक्ष आठ प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें ग्राम पंचायतों में कार्यरत कनिष्ठ एवं वरिष्ठ सहायकों को ग्राम विकास अधिकारी के समान अधिकार देना, पंचायत कर्मचारियों के लिए उत्तराखंड मॉडल लागू करना, पदोन्नति के अवसर बढ़ाना, अंतरजिला स्थानांतरण नीति लागू करना, नोशनल लाभ प्रदान करना, वेतन विसंगतियां दूर करना, हार्ड ड्यूटी अलाउंस लागू करना तथा ग्रामीण विकास राज्य सेवा में 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के लिए आरक्षित करने की मांग शामिल है।

25 सितंबर को सौंपेंगे ज्ञापन

आंदोलन के प्रथम चरण में 25 सितंबर को मुख्यमंत्री, पंचायतीराज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, मुख्य सचिव तथा विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया के आधार पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की अगली रणनीति लागू की जाएगी।

एमएलएसयू में बीए प्रथम सेमेस्टर की रिक्त सीटों पर दोबारा प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 8 जुलाई तक होंगे ऑनलाइन आवेदन

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 2 जुलाई। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीए प्रथम सेमेस्टर (नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम) की रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। प्रथम चरण के प्रवेश के बाद विभिन्न विषयों में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए 2 से 8 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महाविद्यालय प्रशासन के अनुसार रिक्त सीटों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की वरीयता सूची 10 जुलाई को महाविद्यालय के सूचना पट्ट एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके बाद 15 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक महाविद्यालय परिसर में वरीयता के आधार पर काउंसलिंग आयोजित होगी। महाविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही आवेदन कर रखा है, वे भी अपने पूर्व आवेदन पत्र और निर्धारित शुल्क के साथ काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। विषयवार रिक्त सीटों और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय प्रशासन ने इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने और काउंसलिंग में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने की अपील की है।

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा।